International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 1; Issue 2; March 2016; Page No. 47-48

औपनिवेशिक शासन में कृषि

Tulsi Chouhan

Assistant Professor, Department of History, Vivekananda College, Delhi University, Delhi, India

प्रस्तावना

यह सर्वमान्य है कि अंग्रेजी सरकार का भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने का एक ही उद्देश्य था और वह था भारत से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए। और औपनिवेशिक सरकार ने अपने तमाम निर्णय लेते हुए उपरोक्त विचार को ही केंद्र में रखा। और फिर चाहे किसी राज्य से राजनैतिक संबंधों की एक रूपरेखा तैयार करनी हो या फिर राज्य के किसी वर्ग का राज्य सरकार से संबंध निर्धारित करना हो औपनिवेशिक सरकार स्वहित से इत्र किसी भी बात पर विचार नहीं करती थी। भारतीय कृषि और कृषक के विषय में तो यह बात और भी सत्य प्रतीत होती थी।

भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे धनी प्रांत को जीतते ही अंग्रेजों ने वहां भूराजस्व की वसूली हेतु स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। इसके पीछे औपनिवेशिक इतिहास कार इस बात के बड़े-बड़े दावे करते हैं कि स्थायी बंदोबस्त को भारतीय कृषि और कृषकों की बदहाली को दूर करने या भारतीय कृषि और कृषकों की आर्थिक खुशहाली को बढ़ाने के लिए किया गया था।

किंतु यह दावा सत्य नहीं है कि औपनिवेशिक हुकूमत यदि कृषि और कृषक के विकास के लिए उत्सुक होती तो लगान की दर एक तिहाई से अधिक न होती जो अंग्रेजों ने 50 प्रतिशत से अधिक रखी थी।

इतना ही नहीं जब इस प्रथा के हानिकारक प्रभाव सामने आए तो इसके स्थान पर रैयतवाड़ी नामक एक नई व्यवस्था को ईजात किया गया किंतु इनमें भी कर की दर में कोई कमी नहीं की गई। कर की मात्रा को 50 प्रतिशत से अधिक बरकरार रखा गया और न ही महलवाड़ी में कम किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का कृषक अब गरीबी और भुखमरी के चंगुल में फंस गया। भूराजस्व चुकाने के लिए उसे प्रति वर्ष महाजन के सामने हाथ फैलाने को मजबूर होना पड़ता है और महाजन के ऋण जाल में जो कृषक फंस जाता तो उसके बाद उसका बच निकलना नामुमकिन हो जाता है।

औपनिवेशिक सरकार की भूराजस्व नीति की एक और विशेषता थी कि और वह थी कर की नगदी वसूली करना। इसके फलस्वरूप कृषि के वाणिज्यकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। वाणिज्यकरण अपने आप में कोई दूषित आर्थिक क्रिया नहीं थी किंतु जिस तरीके से भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण किया जा रहा था उसे किसी भी तरीके से संतोषजनक नहीं माना जा सकता। मानसून पर निर्भर परंपरागत कृषि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कैसे ठहर सकती थी। अंग्रेजों की भूराजस्व नीतियों के परिणाम को समझने में हमें कोई विलंब नहीं होगा यदि हम औपनिवेशिक काल में होने वाले कृषक विद्रोह पर मात्र एक नजर डालें। देश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिसमें कृषक अपनी हृदय विदारक दशा के लिए सरकार से संघर्ष न कर रहा हो। इसी से हम इस बात का अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं कि कृषि और कृषक का कितना विकास हुआ होगा।

जिस देश में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण मात्र इसलिए नहीं किया गया कि रेलवे के निर्माण व रेलवे के जाल बिछाने में निवेश करना अधिक लाभदायक है। जिस देश में सिंचाई, जो कि बुनियादी सुविधा है, की ओर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा था वहां कृषि के विकास की बात ही बेईमानी है।

बढ़ती जनसंख्या व हस्तशिल्प के पतन के कारण कृषि पर निरंतर दबाव बढ़ता चला गया और इसके फलस्वरूप जोतो का विखंडन भी बढ़ता चला गया। भूमि का एक बड़ा प्रतिशत मेड़बंदी व बाड़ बनाने के काम में व्यर्थ हो जाता था। अंत में यदि हम यह कहें कि बार-बार पड़ने वाले अकाल और उनसे मौत के मुंह में समा जाने वाले लाखों लोग या बार-बार खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों का कारण औपनिवेशिक सरकार की कृषि विरोधी नीतियां ही थी तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी।

References

1. Butha Banden Poliell. The land system of British India, 2 vols.
2. PC. Dutt: Economic History of India, 2 vols.
3. Eric Stokes: The peasant and the Raj
4. Morri's Morris D. Indian Economy In the nineteenth century A suympsium.